eISSN 3049-2610

RESEARCH STREAM

A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal

Volume 02, Issue 01, April 2025

उच्च शिक्षा उन्नयन हेतु पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता

डॉ0 ऋचा सिंह राठौर[1]

[1]सहायक प्राध्यापक, रक्षा अध्ययन विभाग, गांधी महाविद्यालय, उरई (जालौन)

Received: 01 April 2025 Accepted & Reviewed: 05 April 2025, Published: 30 April 2025

Abstract

उच्च शिक्षा में वर्तमान में सशक्त कार्य करने की आवश्यकता है। मात्र दस प्रतिशत युवा आबादी ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पा रही है तथा इसमें भी पंजीकृत विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय विद्यार्थी ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट के बाद भी नौकरी योग्य नहीं हैं। उनमें तार्किक क्षमता, अंकगणितीय योग्यता और विज्ञान की समझ निम्न स्तर की है।

हमारी शिक्षा मूलतः किताबी और पारंपरिक पद्धति पर आधारित है। इसने शोधपरक शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध किया है। शिक्षा की गुणवत्ता पाठयक्रम के आधार पर तय की जाती है क्योंकि शिक्षा और पाठ्यक्रम का गहन सम्बन्ध है। शिक्षा प्रक्रिया में तीन प्रमुख घटक– शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठयक्रम होते हैं। इन तीनों का अन्तःसम्बन्ध ही शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करता है। सभी प्रकार के पाठयक्रम भिन्न–भिन्न उदेश्यों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त बिंदुओं के अलोक में यह समझा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का नवीनता और वैज्ञानिकता से युक्त होना कितना आवश्यक है। यदि बेहतर विद्यार्थियों का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है तो शिक्षा को स्तरीय एवं उपयोगी बनाना परमावश्यक है। यह किताबी, रटंत और परीक्षा केन्द्रित शिक्षा पद्धति से संभव नहीं है।

की वर्ड– उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रम, महाविद्यालय, पंजीकरण, शिक्षक, विद्यार्थी, नवाचार

Introduction

उच्च शिक्षा क्षेत्र की स्थिति यह है कि एक तरफ शैक्षिक उन्नयन की नीतियां बनाई जाती हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नित ही कोई न कोई नियम निकाल कर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाये जाने के प्रयास किये जाते हैं दूसरी तरफ खुद उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ देखने को मिलता है। शिक्षा किसी भी मानव को एक न्यायसंगत और समाज के विकास की राष्ट्रीय अवधारणा के लिए प्रेरित करती है। यह उसे वैश्विक मंच तक ले जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समानता, उन्नति आदि के मार्ग खोलती है। आज समूचा विश्व एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो रहा है वहीं दूसरी ओर डाटा साइंस, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्रों में ऐसे कुशल लोगों की आवश्यकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में विविध विषयों में मानक योग्यता रखते हों। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई शिक्षा नीति में भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बनाते हुए इस प्रकार के लक्ष्य शामिल किए गए हैं जो सभी

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ–साथ भाषा, कला, संस्कृति, इतिहास से भी परिचित करा सकें।

उच्च शिक्षा देश के विकास का दर्पण होती है। उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रमों में समग्रता तथा एकरूपता का प्रयास ही इस क्षेत्र को उन्नत करने की दिशा में ले गया है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भी आगे बढ़ने हेतु नीति निर्माण किया जा रहा है। इसके द्वारा एक बहुत महती प्रयास यह किया जा रहा है कि ने केवल प्राथमिक स्तर के बल्कि उच्च शिक्षा स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं की प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा विशेष बात यह है कि विद्यार्थी के समक्ष विषय चयन की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। अब विद्यार्थी बिना किसी तनाव, दवाब के अपने मनपसंद विषयों में अध्ययन कर सकता है। इससे एक तरफ उस विद्यार्थी को मनोनुकूल विषय पढ़ने की स्वतंत्रता होगी, दूसरी तरफ वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकेगा। इन सभी परिवर्तनों की आवश्यकता इस कारण से और भी अणिक महत्तवपूर्ण समझ आ रही हैं क्योंकि ''उच्च शिक्षा क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है।''[1] भारतीय उच्च शिक्षा को यदि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में गहरे विचार–विमर्श के पश्चात ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम ना सिर्फ सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य से वंचित हैं बल्कि अपनी विशाल युवा आबादी को भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं। वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा अत्यंत विकट स्थिति से गुजर रही है, जहाँ ना हम अपनी शैक्षिक आबादी को उचित संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम हैं और ना ही उच्चस्तरीय गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं। वर्तमान शैक्षिक आधारभूत संरचना में मात्र 10 प्रतिशत युवा आबादी ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पा रही है तथा इसमें भी पंजीकृत विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है।

''भारत में लगभग 800 से अधिक विश्वविद्यालय तथा 40000 से भी अधिक महाविद्यालय हैं।''[2] इसके अलावा 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 125 डीम्ड विश्वविद्यालय, 361 निजी विश्वविद्यालय, आईआईएम, आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान शामिल हैं किन्तु इनमें से कोई भी उच्च रैंकिंग में नहीं है। वर्ष 2016–17 में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग 8000 शैक्षणिक ऐसे हैं जिनमें छात्रों के पंजीकरण की संख्या 100 से भी कम है तथा 40 प्रतिशत संस्थान ऐसे हैं जिनमें एक ही प्रोग्राम अर्थात सिर्फ बी0ए0 अथवा बी0एस–सी0 की पढ़ाई होती है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी समस्या सकल नामांकन की है। हमारे ''देश में सकल नामांकन 27.1 प्रतिशत है''[3] जो विकसित देशों के साथ–साथ अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। अमेरिका जैसे देशों में यह 83 प्रतिशत है। यद्यपि हमारी उच्च शिक्षा अमेरिका और चीन के बाद आकार में तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है तथापि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हमारा कोई स्थान नहीं है।

देश की स्वतन्त्रता का एक लम्बा समय निकल जाने के बाद भी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग मैकाले सिंड्रोम से ग्रसित है और ब्रिटिश मॉडल के यूनिवर्सिटी सिस्टम पर आधारित है जो भारतीय आवश्यकताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। हमारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से निकले विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप वास्तविक योग्यता धारित नहीं करते हैं। एक सर्वे ने यह संकेत दिया

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025
WWW.RESEARCHSTREAM.IJARMS.ORG

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

कि भारतीय विद्यार्थी ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री के बाद भी नौकरी देने योग्य नहीं हैं। उनमें साधारण तार्किक क्षमता, अंकगणितीय योग्यता और विज्ञान की समझ बेहद निम्न स्तर की है जो उन्हें प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हाशिए पर खड़ी कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले युवा प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव ना सिर्फ उनके भविष्य पर बल्कि देश के भविष्य पर भी पड़ रहा है। शिक्षक–छात्र अनुपात में असंतुलन इसका एक प्रमुख कारण है। वर्तमान में जहाँ हमारे देश के आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 15 से 20 प्रतिशत तक शिक्षकों के पद खाली हैं वहीं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की दशा इससे भी अधिक दयनीय है। शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता ना होने के साथ–साथ आधारभूत संरचनाओं की कमी होना भी इस स्तरहीनता का प्रमुख कारण है। एक अनुमान है कि ''वर्ष 2030 तक लगभग 14 करोड़ छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा में पंजीकृत होंगे।''[4] क्या हम उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं?

भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो स्कूली एवं महाविद्यालय स्तर पर दी जा रही है, उसका उद्देश्य पाठयक्रम न होकर उसका प्रसार है। इस कारण अधिकांश विद्यालय एवं महाविद्यालय उन्हीं पुराने विषयों को प्रमुखता देते हैं जो सरल प्रतीत होते हैं। परम्परागत विषयों से अलग न सोचने की प्रवृति गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। शिक्षा की गुणवत्ता के तीन प्रमुख आधार निम्नवत माने जाते हैं।

1– पाठ्यक्रम (Curriculum)

2– निर्देश का माध्यम (Medium of Instruction)

3– मूल्यांकन (Assessment)

हमारी शिक्षा मूलतः किताबी शिक्षा और पारम्परिक पद्धति पर आधारित है। परीक्षा व्यवस्था भी अंकों की चूहादौड़ पर आधारित है। ज्ञान के स्थान पर मेरिट महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी रटंत प्रक्रिया द्वारा प्राप्त अंकों को ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। इस मानसिकता ने शोधपरक शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध किया है। विश्वविद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रम नितांत पुराने हैं तथा उन्हें पढ़ाने के तरीके भी उबाऊ हैं।

प्राइमरी शिक्षा की भी यही दशा है। शिक्षा को ज्ञानपरक और रुचिकर बनाने का एकमात्र विकल्प कक्षा के मानसिक स्तर और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नवीन तकनीकों और परम्परागत शिक्षण विधियों से इतर नवाचार आधारित पद्धति अपनाना है। इसमें शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर नवाचार और शोधपरक शिक्षा को वित्तीय और तकनीकी साधनों के साथ जोड़ कर देखा जाता है जो एक अपरिपक्व दृष्टिकोण को दर्शाती है।

यहाँ पर एक केस स्टडी के रूप में छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विद्यालय शुक्लाभाठा, विकासखंड मनपुर में तैनात सहायक शिक्षक श्री संतोष कुमार तारक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिन्होंने कोरोनाकाल में अपने विद्यार्थियों के लिए नवाचार आधारित एक ऐसी पद्धति अपनाई जिससे आदिवासी क्षेत्रों के बालक, बालिकाओं को उनके घर पर ही पढ़ाया जा सके और यह शिक्षा रुचिकर भी हो। सर्वप्रथम श्री तारक द्वारा शिक्षकों की एक टीम बनाई गई जिसने समस्या को पहचान कर बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया। इसी क्रम में एक बुक बैंक का भी निर्माण किया गया जिसमें कई प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध करवाई गईं। विद्यार्थियों के लेखन कौशल का विकास करने हेतु पारंपरिक तरीके से हट कर

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610

RESEARCH STREAM

A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal

Volume 02, Issue 01, April 2025

बालक–बालिकाओ को दीवारों पर लिखने हेतु छोटे–छोटे प्रोजेक्ट्स दिए गये। बच्चों को राशन वितरण के कार्य में लगाया गया। अपने परिवार का विवरण, घर और गाँव का नक्शा बनाने जैसे छोटे–छोटे प्रोजेक्ट्स पर विद्यार्थियों ने मन लगा कर कार्य किया। इस प्रकार कोरोनाकाल में उनकी पढाई न सिर्फ अबाधित रही बल्कि उनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन भी किया गया। यह सिर्फ एक प्रयास है यह बताने का कि किस प्रकार एक शिक्षक की सोच पारम्परिक कक्षाओं को अ पारम्परिक कक्षाओं में बदलकर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। नवाचार आधारित ऐसी व्यवस्थाएँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण साबित होंगी।

शिक्षा क्षेत्र किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकता है जब उसकी बुनियादी समस्याओं को समझा जाये। भारतीय सन्दर्भ में उच्च शिक्षा की समस्याओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है–

1– आधारभूत संरचनाओं का अभाव
2– गुणवत्ता पर ध्यान ना दिया जाना
3– पर्याप्त बजट का अभाव
4– नवाचार और शोध पर ध्यान ना देना
5– असंतुलित छात्र–शिक्षक अनुपात
6– पाठ्यक्रम का स्तरहीन और जड़ होना
7– ज्ञान प्रदान करने के स्थान पर डिग्री बाँटने की मशीन में परिवर्तित होना
8– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक अन्तर होना
9– अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप
10– वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल ना होना

उच्च शिक्षा क्षेत्र की उक्त समस्याओं के सन्दर्भ में विचार किया जाये तो इनमें प्रमुख रूप से छात्र–शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio) एक महत्वपूर्ण विषय है जो सीधे–सीधे कक्षा के स्तर को प्रभावित करता है। इसके चलते पाठ्यक्रम के निर्माण, उसके क्रियान्वयन आदि को लेकर भी समस्या उत्पन्न होती है। UNESCO की State of Education Report for India 2021 भारत में छात्र–शिक्षक अनुपात पर प्रकाश डालती है।

इस रिपोर्ट के अनुसार ''कुछ राज्यों में 10 से 15 प्रतिशत स्कूल एक ही अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। 11.16 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इनमें से 69 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हैं।''[5] वैसे तो ''शिक्षा का अधिकार कानून के द्वारा PTR के मानक निर्धारित किये गये हैं, जो ग्रेड 1–5 (प्राइमरी) हेतु 30:1, ग्रेड 6–8 (अपर प्राइमरी/मिडिल) हेतु 35:1 होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय छात्र–शिक्षक अनुपात को देखा जाये तो यह 26:1 है,''[6] (2018/19 UDISE) जो काफी अच्छा प्रतीत होता है किन्तु यदि इसे अलग–अलग कर विश्लेषित किया जाये तो यह असंतुलित और तय मानकों से पीछे है। सीनियर सेकंडरी में यह 47:1 है। ये उपलब्ध आँकड़े शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत जैसे विषयों को छोड़ कर हैं। इन विषयों से सम्बंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025
WWW.RESEARCHSTREAM.IJARMS.ORG

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

शिक्षकों के रिक्त पद भी एक समस्या है तथा बड़े पैमाने पर अस्थाई शिक्षकों की भर्ती गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला दूसरा बड़ा कारण है। बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों का स्तर एवं शिक्षकों की उपलब्धता भी बेहतर होना चाहिए। UNESCO की ''भारत सम्बन्धी रिपोर्ट 2021 का शीर्षक भी NO TEACHER NO CLASS है''[7] जो यही सन्देश देता है कि शिक्षक–छात्र अनुपात यदि संतुलित नहीं होगा तो गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बेहतर शिक्षक ही बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अनुपात सही रहने पर ही एक शिक्षक कक्षा के समस्त छात्रों पर ध्यान दे सकता है तथा छात्र की आवश्यकता के अनुरूप मार्गदर्शन कर सकता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि NEP के समग्र उदेश्यों को प्राप्त करने हेतु छात्र–शिक्षक अनुपात को तय मानकों के अनुरूप लाया जाये। इसके अभाव में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है।

भारतीय उच्च शिक्षा सर्वाधिक बीमार व्यवस्थाओं में से एक है। आकार और संख्या की दृष्टि से यह विशाल भले हो किन्तु गुणवत्ता से मीलों दूर है। गुणवत्ता से समझौता हमारी प्रवृत्ति बन चुका है। इसी सोच के कारण किसी भी सुधार अथवा परिवर्तन के प्रयासों को अस्वीकरण एवं आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अब बदली हुई परिस्थितियों में हमें वैश्विक मानदंडों के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। SDG–4 द्वारा समग्र, समान, निष्पक्ष, जीवनपर्यंत सीखने के अवसर उपलब्ध कराने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा को ध्येय माना गया है।'भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी–4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन–पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य है।''[8] यदि भारतीय संदर्भ में बात करें तो शिक्षा को निजी और सरकारी दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जिनका अनुपात क्रमशः 5:7 है। सरकारी क्षेत्र की भागीदारी बड़ी है किन्तु वह गुणवत्ता बनाये रखने में असफल साबित हुआ है। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा अपर्याप्त एवं अधूरी है। शिक्षकों की कमी और उनके द्वारा प्रयोग की जा रही शिक्षण तकनीक बेहद पुरानी एवं निम्न स्तरीय है जो आधुनिक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी अधिक चिंताजनक है। सरकारी क्षेत्र निम्न स्तरीय सुविधाओं और शिक्षकों से जूझ रहे हैं वहीं निजी क्षेत्र बेहतर सुविधायें तो उपलब्ध करा रहे हैं किन्तु अत्यधिक मँहगे हैं और गरीबों की पहुँच से बाहर हैं। भारत की लगभग 37 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। ऐसे में समग्र, समान शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। मँहगी शिक्षा आम लोगों की पहुँच से बाहर होने के साथ–साथ सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को भी मूर्त रूप देने में सक्षम नहीं है। निजी क्षेत्र भी विशाल आबादी की ज़रूरतें पूरी करने में अक्षम है। ऐसे में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश के साथ–साथ बेहतर निगरानी व्यवस्था और तंत्र को खड़ा करने की आवश्यकता है।

शिक्षा की गुणवत्ता पाठयक्रम की संरचना और उपयोगिता के आधार पर तय की जाती है। शिक्षा और पाठ्यक्रम का गहन सम्बन्ध है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ''शिक्षा प्रक्रिया में तीन प्रमुख घटक होते है– 1–शिक्षक 2–शिक्षार्थी 3–पाठयक्रम,''[9] इन तीनों का अन्तःसम्बन्ध ही शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करता है। इस आधार पर ''पाठयक्रम भी भिन्न–भिन्न प्रकार का होता है''[10]–

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025
WWW.RESEARCHSTREAM.IJARMS.ORG

1– विषय केन्द्रित (Subject Centred Curriculam)

2– परम्परागत (Traditional Curriculam)

3– छात्र केन्द्रित (Student Centred Curriculam)

4– कार्य केन्द्रित (Work/Activity Centred Curriculam)

5– अनुभव केन्द्रित (Experience Centred Curriculam)

6– कोर पाठ्यक्रम (Core Curriculam)

ये सभी प्रकार के पाठयक्रम भिन्न–भिन्न उदेश्यों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के पाठयक्रम की जड़ता का शिकार होने के कारण अधिकांश पाठयक्रम, भले ही वे माध्यमिक, उच्च शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा से जुड़े हों, में बदलाव की एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इस कारण पाठयक्रम न तो प्रतिस्पर्धा और न ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी रह गये हैं। तमाम उच्च शिक्षण संस्थान और तकनीकी संस्थान भी इसी कारण शैक्षिक मानदंडों एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं।

पाठ्यक्रम की समस्याओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है–

1– किताबी ज्ञान को प्रोत्साहित करने वाला

2– परीक्षा केन्द्रित

3– सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से अनुपयोगी

4– अधिगम के सिद्धांतों के विपरीत प्रवृत्ति पर आधारित

5– वैयक्तिक विभिन्नता की उपेक्षा

6– वैज्ञानिकता का लोप

7– परंपरागामी एवं ऐतिहासिक स्वरूप पर आधारित

8– छात्रों एवं शिक्षक दोनों के लिए ही उबाऊ और अरुचिकर

उपरोक्त बिंदुओं के अलोक में यह समझा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का नवीनता और वैज्ञानिकता से युक्त होना कितना आवश्यक है। यदि बेहतर विद्यार्थियों का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है तो शिक्षा को स्तरीय एवं उपयोगी बनाना परमावश्यक है। यह किताबी, रटंत और परीक्षा केन्द्रित शिक्षा पद्धति से संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक संस्थानों के मूल स्तर तक जाकर इसके लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि कैसे बच्चों में प्रयोगात्मक क्षमता का विकास करने योग्य पाठ्यक्रम निर्मित किया जा सके। उनको किताबी ज्ञान से या फिर किताबी पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने मात्र की मानसिकता से बाहर लाने की आवश्यकता है। इसके लिए उनकी स्थानीय जानकारियों और विषयों के साथ वहाँ के भौगोलिक वातावरण को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

eISSN 3049-2610

RESEARCH STREAM

A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal

Volume 02, Issue 01, April 2025

सन्दर्भ सूची–

1–बीबीसी, https://www.bbc.com/hindi/india/2013/10/131013_higher_education_big_picture_rf_pk

2– The Statesman, https://www.thestatesman.com/supplements/campus/higher-education-a-long-way-to-go-1502744204.html

3– दैनिक भास्कर, https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/ajmer/news/our-gross-enrollment-ratio-in-higher-education-in-the-world-is-271-this-is-worrying-130931718.html

4– राष्ट्रीय हिन्दी मेल, https://rashtriyahindimail.in/posts/36702

5–वेबदुनिया, https://hindi.webdunia.com/latest-deutsche-welle-news/11-lakh-teacher-posts-vacant-in-schools-in-india-121100800010_1.html

6– **Press Information Bureau, Government of India,** https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=158326

7– दृष्टि, https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/2021-state-of-the-education-report-for-india-unesco

8– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ड्राफ्ट, पृष्ठ 3, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

9– सफलता, https://www.safalta.com/doubts/teaching-exams/

10– रुटीन स्टडी, https://routinestudy.com/pathyakram-ke-prakar

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025